एमएसएमई के लिए हर जिले में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : राज्य सरकार ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को और सशक्त बनाने पर जोर दिया है। इस क्षेत्र के लिए बजट में 3,822 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है, जो 2025-26 के आवंटन की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

एमएसएमई क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक जोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एमएसएमई के लिए राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 575 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

75 करोड़ का आवंटन एक जिला एक व्यंजन योजना के लिए हुआ

उत्तर प्रदेश पहले से ही 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या के आधार पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

राज्य के निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की 40 प्रतिशत भागीदारी है। इसीलिए सरकार का फोकस इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित करने पर है। वर्ष 1960 के बाद से एमएसएमई के लिए विशेष तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर पहली बार काम किया जा रहा है।

पूरी दुनिया में पहुंचेगा यूपी के व्यंजनों का स्वाद

विभिन्न देशों तक उप्र के स्वाद को पहुंचाने के लिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर ओडीओपी की तर्ज पर शुरू की गई एक जिला एक व्यंजन योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट में 75 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इस योजना के तहत सभी जिलों से चयनित व्यंजनों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा।

कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 5,041 करोड़ रुपये

सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में हथकरघा, वस्त्र उद्योग और खादी ग्रामोद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। साथ ही वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में परिधान का हब विकसित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी।

3,822 करोड़ का बजट एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया आवंटित

575 करोड़ रुपये सरदार पटेल रोजगार व औद्योगिक जोन के लिए मिले

MAGZTER Clipped from Dainik Jagran Lucknow - February 12, 2026
Read it digitally on Magzter